ALL INDIA FORUM AGAINST PRIVATISATION (AIFAP)

AN ATTACK ON ONE IS AN ATTACK ON ALL!

Website: https://aifap.org.in
Email: contact@aifap.org.in

WhatsApp Number:
+918454018757

16 फरवरी 2022

प्रति,
श्री गोपाल दत्त जोशी,
महासचिव,
यूनियन टेरिटरी (यूटी) पावरमैन यूनियन, चंडीगढ़

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) की ओर से हम उस संघर्ष के लिए अपना तहे दिल से समर्थन व्यक्त करते हैं जो आपका यूनियन चंडीगढ़ बिजली विभाग को एक निजी कंपनी को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए कर रहा है।

केंद्र सरकार के निर्णय के वास्तविक जनविरोधी, मजदूर विरोधी और समाज विरोधी चरित्र को उजागर करने के आपके संयुक्त प्रयासों के लिए हम आपकी सराहना करते हैं। केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए सफलतापूर्वक जनमत तैयार करने के लिए हम आपको बधाई देते हैं।

आपने निजीकरण के वास्तविक जनविरोधी, समाज विरोधी चरित्र को विस्तार से समझाते हुए उजागर किया है कि:

- लाइन लॉस *(पारेषण के दौरान क्षति)* केंद्र सरकार के 15% के मानक से काफी नीचे और 10% से कम है।

- अच्छी सेवा के लिए विभाग को अनेक पुरस्कार मिले हैं।

- पिछले 5 वर्षों में विभाग द्वारा बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, उलटा इस वर्ष दरों में कमी की गई है और 150 यूनिट तक बिजली की दर 2.50 रुपये और अधिकतम 4.50 रुपये है। लेकिन जब विभाग का निजीकरण होगा तो दरों में भारी वृद्धि होना तय है। वास्तव में Eminent नामक कंपनी को सरकार बेचने की योजना बना रही है, और यह कंपनी कोलकता में 150 यूनिट तक प्रति यूनिट रु. 7.16 तक और 300 यूनिट से अधिक प्रति यूनिट 8.92 रुपये की दर वसूल कर रही है!

- पिछले 5 साल में एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा होने के बावजूद विभाग 871 करोड़ रुपए में बिक रहा है।

- भले ही विभाग की कुल संपत्ति का बाजार मूल्य 20,000-25,000 करोड़ रुपये के बीच है, लेकिन इसे निजी कंपनी को मात्र 871 करोड़ रुपये में सौंपने की योजना है। और तो और, विशाल भूमि को 1/- रूपये प्रतिमाह के पट्टे पर निजी कम्पनी को दिये जाने का प्रस्ताव है !

आपने बहुत सही ढंग से इसकी निंदा की है कि इतना कठोर निर्णय लेने से पहले मुख्य हितधारकों यानी उपभोक्ताओं और मज़दूरों से बिल्कुल भी सलाह नहीं ली गई थी। वास्तव में, जैसा कि आपने बताया है, कर्मचारियों और रेजिडेंट (निवासी) एसोसिएशनों के विरोध की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है।

यह भी सभी जानते हैं कि निजीकरण के बाद कॉर्पोरेट मालिक मौजूदा कर्मचारियों पर हमला करते हैं। वे श्रमिकों को अधिकारों से वंचित करते हैं और बड़े पैमाने पर छंटनी करते हैं, तथा सस्ते दरों पर अकुशल ठेका श्रमिकों को किराए पर लेते हैं। इस से सीधे श्रमिकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी वे नुकसान पहुंचाते हैं।

पूरे देश में विभिन्न बिजली क्षेत्र के संगठनों और श्रमिकों, अधिकारियों और इंजीनियरों के संघों, किसान संगठनों और जन संगठनों के दृढ़ विरोध के कारण, केंद्र सरकार बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 या 2021 में नहीं पारित कर पाई। लेकिन सरकार बड़े पैमाने पर श्रमिकों और लोगों की मांगों को कुचल रही है और केंद्र शासित प्रदेशों में जबरन निजीकरण को बढ़ावा दे रही है।

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी सहित देश के कई हिस्सों में बिजली कर्मचारी निजी इजारेदारों को लोगों की लूट बढ़ाने और श्रमिकों का शोषण करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार की नापाक योजनाओं को विफल करने में सफल रहे हैं।

सबसे पहले उन्हें इसलिए सफलता मिली है क्योंकि पूरे देश के बिजली कर्मचारियों ने विचारधारा और संलग्नता की सभी बाधाओं को पार कर बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCCOEEE) के बैनर तले एकजुट हो गए हैं। NCCOEEE और उसके घटकों के नेता पूरे देश में बिजली कर्मचारियों के संघर्षों का सक्रिय रूप से समर्थन करते रहे हैं।

एक अन्य कारक जो इन संघर्षों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहा है, वह यह है कि उपभोक्ताओं को जिनकी संख्या करोड़ों में है, उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से समझाया है कि बिजली का निजीकरण उनके हितों के लिए हानिकारक क्यों है। उसी खतरे का

सामना कर रहे चंडीगढ़ में भी जन संगठनों का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया गया है।

AIFAP के सभी घटक आपके यूनियन द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष का तहे दिल से समर्थन करते हैं।

आपके साथ एकजुटता में,

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम

घटक (अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में)

1) एयर इंडिया एम्प्लोयीज यूनियन (AIEU),
2) एयर इंडिया सर्विस इंजिनियर्स एसिओसेशन (AISEA),
3) ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसिओसेशन (AIBOA),
4) ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (AICWF),
5) ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी ऑर्गेनाजेशंस (ऑल इंडिया परिसंघ),
6) ऑल इंडिया डिफेन्स एम्पलोयीज फेडरेशन (AIDEF),
7) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्पलोयीज (AIFEE),
8) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (AIFOPDE),
9) ऑल इंडिया गाईस काउंसिल (AIGC),
10) ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA),
11) ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम (NPS) एम्प्लोयीज फेडरेशन,
12) ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लोयीज एसोसिएशन - उत्तर रेलवे,
13) ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (AIPMA),
14) ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (AIPDWF),
15) ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF),
16) ऑल इंडिया रेलवे एम्पलोयीज कॉन्फेडरेशन (AIREC) - पश्चिमी क्षेत्र,
17) ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (AIRTU),
18) ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF),
19) ऑल इंडिया शेडूल्ड कास्ट शेडूल्ड ट्राईब एम्प्लोयीज एसिओसेशन (AISCSTREA),
20) ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (AISMA),
21) ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन (AITCA),
22) आंध्र प्रदेश स्टेट पॉवर एम्प्लोयीज जॉइंट एक्शन कमिटी (APSPEJAC),

23) बहुजन समाजवादी मंच (BSM),
24) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) एम्प्लोयीज एसिओसेशन, पलक्कड़, केरल
25) भारत पेट्रोलियम टेक्नीकल और नौन- टेक्नीकल एम्पलोयीज एसोसिएशन (BPTNTEA) - मुंबई रिफाइनरी,
26) भारतीय रेलवे मज़दूर यूनियन (BRMU) एसडव्लू रेलवे, हुबली,
27) बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) एम्प्लोयीज यूनियन,
28) बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) कामगार संघटना,
29) चित्तरंजन लोको वर्क्स (CLW) रेलवेमेन्स यूनियन, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
30) चित्तरंजन रेलवेमेन्स कांग्रेस (CRMC), चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
31) कोचीन रिफाइनरी एम्पलोयीज एसोसिएशन (CREA-INTUC),
32) कोचीन रिफायनरीज वर्कर्स एसोसिएशन (CRWA)-CITU,
33) कन्टेनर कॉर्पोरेशन (CONCOR) एम्पलोयीज यूनियन,
34) दक्षिण रेलवे एम्पलोयीज यूनियन (DREU),
35) डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स (DMW) रेलवेमेन्स यूनियन, पटियाला, पंजाब,
36) डीजल लोको वर्क्स (DLW) मेन्स यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
37) डीएमडव्ल्यू रेलवे वर्कर्स यूनियन (DMWRWU), पटियाला, पंजाब,
38) इलेक्ट्रीसिटी एम्पलोयीज फेडरेशन ऑफ इंडिया (EEFI),
39) हिंद खदान मजदूर फेडरेशन (HKMF),
40) हिंद मज़दूर सभा (HMS) - तेलंगाना,
41) हिंदुस्तान पेट्रोलियम एम्पलोयीज यूनियन, विशाखापत्तनम रिफाइनरी,
42) इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (INWEF),
43) इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाइजेशन (IRLRO),
44) इंडियन रेलवे टिकटचेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (IRTCSO),
45) इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मजदूर संघ (ICFMS), चेन्नई, तमिलनाडु,
46) इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (ICF) लेबर यूनियन, चेन्नई, तमिलनाडु,
47) जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लोयीज एंड इंजीनियर्स कॉर्डिनेशन कमिटी (JKPEECC),
48) जॉइंट एक्शन फ्रंट ऑफ़ पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियनस ऑफ़ बैंगलोर,
49) कामगार एकता कमिटी (KEC)/मजदूर एकता कमिटी (MEC)/तोयिलाली ओट्टूमइ इयक्कम (TOI),
50) लोक राज संगठन (LRS),

51) मध्य प्रदेश यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ पॉवर एम्प्लोयीज इंजीनियर्स,
52) महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (MSBEF),
53) महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (AITUC),
54) मेन्स कांग्रेस डीजल लोको वर्क्स (MCDLW) वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
55) मुंबई एवं उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ,
56) नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR),
57) नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम एम्पलोयीज (NFTE)-BSNL,
58) नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS),
59) नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (NRMU), मध्य रेलवे/कोंकण रेलवे,
60) नीलाचल एक्जिक्यूटिव्ज एसोसिएशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL),
61) पोर्ट, डॉक एंड वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन (AITUC),
62) पुरोगामी महिला संगठन (PMS),
63) रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, कपूरथला, पंजाब,
64) रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
65) रेल कोच फैक्ट्री मजदूर यूनियन (RCFMU), कपूरथला, पंजाब,
66) रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस (RCFMC), रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
67) रेल व्हील फैक्ट्री (RWF) मजदूर यूनियन, बैंगलोर, कर्नाटक,
68) रेल व्हील फैक्ट्री कार्मिक संघ (RWFKS), बैंगलोर, कर्नाटक,
69) रिसर्च डिजाइन और स्टेंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (RDSO) कर्मचारी संघ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,
70) संचार निगम एक्जिक्यूटिव्ज एसोसिएशन (SNEA)-BSNL,
71) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ऑफिसर्स एसोसिएशन,
72) सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन (AITUC),
73) सिंगारेनी माइनर्स एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन (HMS) - तेलंगाना,
74) सबोर्डिनेट इंजीनियर्स एसिओसेशन (एम्एसईबी),
75) सूरत ट्रेड यूनियन कौंसिल (STUC),
76) टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट मुंबई (TDF),
77) यूनियन टेरीटरी (यूटी) पॉवरमेन्स यूनियन, चंडीगढ़,
78) अनऔर्गेनाईज्द वर्कर्स एंड एमप्लोयीज कॉग्रेस,
79) वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (CITU),
80) वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लोयीज यूनियन (WCREU).